

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

नन्दकिशोर गोयल व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान

एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 351/1997
अन्तर्गत धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 27.8.97 पारित विशिष्ट न्यायाधीश,
आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
सीकर, जिसके द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक
वस्तु अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया गया।

आदेश दिनांक

मार्च 13, 2009

उपस्थित:
माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

सुश्री गायत्री राठौड़ एवं श्री विकास जैन, अधिवक्तागण प्रार्थीगण।
श्री पीयूष कुमार, लोक अभियोजक।

न्यायालय द्वारा:

प्रार्थीगण की ओर से यह दांडिक निगरानी याचिका विशिष्ट न्यायाधीश,
आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), सीकर द्वारा पारित
आदेश दिनांक 27.8.97 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण के
विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ऊर्वरक नियंत्रण आदेश,
1985 के वाक्यांश 19(1)(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व
7 के अन्तर्गत एक परिवादपत्र विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु
अधिनियम, सीकर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मैसर्स

भारत बीज भण्डार कोर्ट रोड, सीकर मालिक रुपचन्द ने अमानक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट (शक्ति ब्राण्ड) का भण्डारण एवं विक्रय किया। थोक विक्रेता मैसर्स बैनारा ब्रदर्स राजेन्द्र काम्पलेक्स, लालसोट जिला दौसा ने अपने विक्रयपत्र दिनांक 17.6.96 द्वारा अमानक उर्वरक का संभरण मैसर्स भारत बीज भण्डार कोर्ट रोड, सीकर को किया है। उक्त वितरक फर्म के श्री अतुलकुमार जैन प्रतिष्ठान के मालिक भी इसमें दोषी हैं। राजस्थान एग्रो केमिको ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि., बाबू टीबा का रास्ता, मोती कटला बाजार, जयपुर में अपने विक्रयपत्र दिनांक 21.5.96 के आधार पर द्वारा मैसर्स बैनारा ब्रदर्स के उक्त अमानक उर्वरक का संभरण किया गया है जिससे उक्त प्रतिष्ठान उर्वरक विक्रय का दोषी है। विनिर्माता मैसर्स शक्ति फर्टिलाइजर्स ने अमानक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट (शक्ति ब्राण्ड) का मेन्युफेक्चरर जिसके द्वारा उक्त निर्माण एवं संभरण किया है जो नियंत्रण आदेश, 1985 के वाक्यांश 19 का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(1)(अ)(11) में दण्डनीय अपराध है।

विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), सीकर ने अपने आदेश दिनांक 27.8.97 के द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण की ओर से यह दांडिक निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण सुश्री गायत्री राठौड़ एवं श्री विकास जैन ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का नाम परिवादपत्र में अंकित नहीं था, इसके बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया है, जो गलत है। उनका यह भी तर्क है कि प्रसंज्ञान लेते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा और बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रसंज्ञान ले लिया, जो विधि विरुद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण का नाम बाद में जोड़ा गया है। अतः आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार ने प्रार्थीगण के विद्वान

अधिवक्तागण के तर्कों एवं प्रार्थना का घोर विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई के निर्देश दिये जावें।

अतः विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.97 को अपास्त करते हुए उक्त न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से एक माह की अवधि में दोनों पक्षों की पुनः सुनवाई कर विधि अनुसार आदेश पारित करे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड शीघ्र वापिस भेजा जावे। यदि इसके उपरान्त वे पाते हैं कि प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई आरोप बनते हैं तो ऐसे आरोप लगाकर विचारण की कार्यवाही त्वरित गति से सम्पन्न करे। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश